राज्य सरकार वंचित वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है- भजनलाल

राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों के माध्यम से भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत कराए जा रहे हैं

जयपुर, 19 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वंचित वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार इन वर्गों के लिए स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सकें। अंत्योदय की भावना को केन्द्र में रखकर राज्य सरकार नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, ताकि विकसित, समावेशी एवं सशक्त राजस्थान बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ा जा सके।

इसी दिशा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड ने उल्लेखनीय पहल की है। निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजनों के 1 हजार 381 लाभार्थियों को लगभग 20 करोड़ रुपये के रियायती ब्याज पर ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच और इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को स्वरोजगार, व्यवसाय विस्तार और शिक्षा के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना है, जिससे वे रोजगार प्रदाता बन सके।

मुख्यमंत्री के संवेदनशील नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी ऑनलाइन ऋण आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। निर्धारित लक्ष्य 3 हजार 470 के मुकाबले 15 हजार 635 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जो योजना के प्रति आमजन के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, जनवरी 2026 के दौरान जिला स्तरीय ऋण चयन समितियों द्वारा जिलेवार साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। चयनित आवेदकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज पूरे करने के बाद डीबीटी के माध्यम से ऋण राशि सीधे उनके खातों में पहुंच जाएंगी।

अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के माध्यम से भी ऋण स्वीकृत कराया जा रहा है। इसमें लक्ष्य 3 हजार 400 के विरुद्ध अब तक 2 हजार 670 व्यक्तियों को विभिन्न बैंकों से ऋण स्वीकृत कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत पात्र व्यक्तियों को प्रोजेक्ट लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 452 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन ऋण आवेदन प्रक्रिया शुरु की गई थी। इसमें निर्धारित लक्ष्य 3,470 के मुकाबले अब तक 15,635 आवेदन योजना के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।**

कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने की सलाह दी, क्योंकि ऐसा करने पर वरिष्ठ नेता एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े हो सकते थे। केरल कांग्रेस इकाई में वेणुगोपाल बहुत लोकप्रिय नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी के बेहद करीबी होने के कारण उन्हें लगता है कि वे केरल की सत्ता तक पहुंच सकते हैं।राहुल गांधी से 14 जनवरी के बाद एआईसीसी में पुनर्गठन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उसे भी टाल दिया गया है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस की नीति किसी मुख्यमंत्री चेहरे को पहले से प्रोजेक्ट करने की नहीं रही है और यही स्थिति केरल में भी रहेगी। के.सी. वेणुगोपाल एआईसीसी में वह शख्स हैं, जो अधिकांश नियुक्तियों और फैसलों को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने पार्टी का बड़ा हिस्सा उनके भरोसे छोड़ दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वही करते हैं, जो के.सी. वेणुगोपाल कहते हैं। अब तक उनमें वेणुगोपाल के सामने खड़े होने का साहस नहीं दिखा है। इसलिए यह फैसला कि वेणुगोपाल जाएंगे या यहीं रहेंगे, कांग्रेस पार्टी की आंतरिक गतिविधियों और निर्णय प्रक्रिया को पूरी तरह बदल सकता है। एक वरिष्ठ नेता के शब्दों में, "तब तक इंतज़ार करो और देखो।"

राहुल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गांधी स्टेडियम में शुभारंभ करेंगे। गांधी नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुहन सोनकर के आवास जाएंगे और अंत में मनरेगा चौपाल में शामिल होकर लोगों के साथ सीधा संवाद करेंगे। इसके बाद वे रायबरेली से दिल्ली के लिए रवाना हो जायेंगे।

हाई कोर्ट ने एसआई पेपर लीक अपील पर बहस पूरी की, फैसला सुरक्षित

पेपर लीक में एकल पीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट खंडपीठ में कई अपीलें दायर हुई थीं

जयपुर, 19 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में एकलपीठ की ओर से भर्ती रद्द करने और आरपीएससी के सदस्यों व चेयरमैन के खिलाफ टिप्पणी करने के खिलाफ पेश अपील पर खंडपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से 35 दिन पहले प्रश्न पत्र को दूसरे सदस्य रामू राम राइका को दिया था। राइका ने इसे अपनी संतान को दिया, जिससे उनका भर्ती में चयन हो गया। वहीं इस दौरान कटारा ने अपने चालक के बेटे अजय प्रताप सिंह को पेपर दिया। इसके अलावा भतीजे विजय डामोर व राहुल कटारा को भी पेपर उपलब्ध कराया। वहीं दलाल कुंदल को परीक्षा से पांच दिन पहले पेपर दिया गया। इसने अशोक गहलोत के तत्कालीन पीएसओ राजकुमार यादव को यह पेपर दिया। दोनों वकीलों की ओर से कहा गया कि प्रश्न पत्र को हस्तलिखित उत्तर सहित, सोशल मीडिया के जरिए कई लोगों को भेजा गया। वहीं प्रकरण में फिलहाल 89 लोगों के खिलाफ जांच लंबित है और 12 वांछित विदेश चले गए हैं। पुलिस दो साल से जांच कर रही है। ऐसे में दोषियों की छटनी संभव नहीं है। इसलिए एकलपीठ का भर्ती रद्द करने का फैसला सही है। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा गया भर्ती में दोषियों की छंटनी संभव है और सरकार को प्रकरण में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। वहीं चयनित अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि वे पुरानी नौकरी छोडकर आए हैं और जांच में दोषी नहीं पाए गए हैं। ऐसे में भर्ती रद्द करना ठीक नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

- **याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी. सिंह की दलील थी कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से 35 दिन पहले प्रश्न पत्र एक दूसरे सदस्य को दे दिया था। सोशल मीडिया के जरिए कई लोगों को हस्तलिखित उत्तर सहित प्रश्न पत्र भेजे गए थे।**

एसआई पेपर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में आरोपियों और गवाहों की संख्या के साथ ही आरोपियों पर चार्ज तय नहीं होने की स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ता आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित है।

जमानत याचिका में अधिवक्ता सुधीर जैन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता गत 15 मार्च से जेल में बंद है। एसओजी ने उसके खिलाफ आईपीसी सहित, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन का प्रयोग अधिनियम व आईटी एक्ट के तहत जांच कर आरोप पत्र पेश कर दिया है। इस प्रकरण में कुल 133 आरोपी और 150 गवाह हैं। वहीं अभी तक निचली अदालत में उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं किए हैं। याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने रवीन्द्र बाल भारती स्कूल के संचालक राजेश खंडेलवाल से दस लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था। प्रकरण में राजेश खंडेलवाल ने पेपर लीक किया था और उसे सुप्रीम कोर्ट से गत 5 दिसंबर को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में उसका अपराध राजेश खंडेलवाल से गंभीर नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता पर 12 प्रकरण लंबित बताए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से सात मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है और पांच प्रकरणों में वह दोषमुक्त हो चुका है। इसके अलावा, जिन धाराओं में उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया है, उनमें अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है और वह 22 माह जेल में रह चुका है। इसलिए उसे जमानत दी जाए। इ सका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने जमानत याचिका खारिज करने की गुहार की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

'भाजपा के साथ गठबंधन करने से भविष्य खत्म हो जाएगा'

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भाजपा से गठबंधन करने वाले दलों को चेतावनी दी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 जनवरी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोलते हुए विपक्षी दलों को उसके साथ गठबंधन करने के खिलाफ चेताया। उन्होंने कहा कि ऐसे समझौते अल्पकाल के लिये सत्ता भले ही दिला दें, लेकिन लंबे समय के लिये राजनीतिक हाशिए पर धकेल देते हैं।

यहां पत्रकारों से बात करते हुए सिब्बल ने कहा कि भाजपा उन राज्यों में, जहां उसे चुनावी हार की आशंका होती है, छोटे क्षेत्रीय दलों से रणनीतिक गठबंधन करती है और सत्ता में आने के बाद उन्हीं दलों को किनारे कर देती है। उन्होंने कहा, "भाजपा उन राज्यों में छोटे दलों से गठबंधन करती है, जहां उसे लगता है कि वह नहीं जीत पाएगी, और सत्ता में आने के बाद, उन्हीं दलों को हाशिये पर डाल देती है।"

क्षेत्रों के बीच अंतर करते हुए, सिब्बल ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा का कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला होता है, जैसे उत्तर प्रदेश वहाँ वह किसी तरह का समझौता नहीं करती। उन्होंने टिप्पणी की, "जहां कांग्रेस के साथ सीधी टक्कर होती है, वहां वे कभी किसी से समझौता नहीं करते।"

दक्षिण भारत की राजनीति का जिक्र करते हुए सिब्बल ने भाजपा पर तमिलनाडु में अपना आधार बढ़ाने के लिए "मंदिर राजनीति" अपनाने का आरोप लगाया, क्योंकि वहाँ उसे कई बार चुनावी झटके लग चुके हैं। उन्होंने कहा, "अब वे तमिलनाडु में यह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार असफल रहने के बाद, उन्होंने मंदिर राजनीति शुरू की है।" उन्होंने आगे कहा कि केरल और पश्चिम बंगाल में भी पार्टी को लगातार प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में हुई टूट का हवाला देते हुए, सिब्बल ने "अवसरवादी राजनीति" के नतीजों को लेकर चेतावनी दी।

उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का उदाहरण देते हुये कहा, "यह विपक्ष के लिए संदेश होना चाहिए कि उनके (भाजपा) साथ समझौता आपको उपमुख्यमंत्री तो बना सकता है, लेकिन आपका भविष्य खत्म हो जाएगा।" उन्होंने कहा, "अजित पवार के साथ भी यही हुआ, जो किसी एक पक्ष के साथ नहीं टिके और केवल तीन सीटों तक सीमित रह गए। जनता समझती है कि अवसरवादी राजनीति कब की जाती है।"

सिब्बल की यह टिप्पणी महाराष्ट्र के हालिया नगर निकाय चुनावों में भाजपा-शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) गठबंधन की बड़ी जीत के बाद आई है। ज्ञातव्य है कि इन चुनावों में बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) सहित कई निकायों में मजबूत प्रदर्शन कर भाजपा-नेतृत्व वाली महायुति ने स्थानीय शासन में अपना दबदबा और मजबूत किया है।

- **सिब्बल ने कहा, यह गठबंधन कुछ समय के लिए सत्ता दिला सकता है, पर, राजनैतिक भविष्य को खत्म कर सकता है।**
- **सिब्बल ने अजित पवार का हवाला दिया और कहा, वे एनसीपी तोड़कर भाजपा से मिल गए, इससे उपमुख्यमंत्री तो बन गए पर उनकी राजनैतिक संभावनाओं के दरवाजे अब बंद हो रहे हैं।**

'शिव सेना ने मुम्बई को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसी गणित के चलते, शिंदे टीम कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। यदि विपक्ष एकजुट हो जाता है, तो उसे महायुति से सिर्फ आठ पार्षदों के पाला बदलने की जरूरत होगी और वह भाजपा की स्थिति पलट सकता है।

लेकिन क्या शिंदे सेना को सिर्फ ठाकरे परिवार से ही डर है?

उद्धव ठाकरे के मुताबिक, शिंदे दरअसल भाजपा से सशंकित हैं। उन्होंने कहा, जो लोग एक बार पार्टी छोड़ चुके हैं, वे दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं। एनडीए के भीतर मेयर पद को लेकर खींचतान चल रही है। भाजपा अपने किसी पार्षद को मेयर बनाकर राजनीतिक संदेश देना चाहती है, जबकि शिंदे पर शीर्ष पद का दावा करने का दबाव है।

दशकों से मुंबई में शिवसेना का मेयर रहा है और इस बार इसे गंवाना बाल ठाकरे की विरासत पर उनके दावे को कमज़ोर करेगा। शिंदे को पिछले साल राज्य चुनावों के बाद, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और देवेन्द्र फड़णवीस के उपमुख्यमंत्री बनकर संतोष करना पड़ा। अब यदि बीएमसी मेयर का पद भी हाथ से निकल गया तो यह उनकी प्रतिष्ठा के लिए एक और नुकसान होगा और ठाकरे परिवार को मौका मिल जाएगा।

इसीलिए मुंबई के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शिंदे टीम का यह "रिज़ॉर्ट कदम" सिर्फ विपक्ष की योजनाओं को नाकाम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सहयोगी भाजपा को लेकर है।

हालांकि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा है कि मेयर के सवाल पर एनडीए के नेता, जिनमें उनमें वे स्वयं और शिंदे शामिल हैं, मिलकर फैसला करेंगे।

शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र "सामना" के संपादकीय में शिंदे टीम को चुनौती दी गई है। संपादकीय में कहा गया है, "शिवसेना ने मुंबई को 23 मराठी मेयर दिए हैं, क्या यह परंपरा अब भी जारी रहेगी?" संपादकीय में मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे के बीच खुली खींचतान का दावा किया गया है।

संपादकीय के अनुसार, ठाकरे भाइयों ने मुंबई की रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया। इसमें कहा गया है, "पहचान की इस लड़ाई का इतिहास नए सिरे से लिखा जाएगा।

शिवसेना (यूबीटी) ने आरोप लगाया कि फडणवीस का चुनाव जीतने का आत्मविश्वास विकास कार्यों से नहीं, बल्कि अपार धन और शक्ति से आया है। पार्टी ने कहा, "इस आत्मविश्वास का विकास से कोई लेना-देना नहीं है, यह पूरी तरह मशीनों, पैसे के मंत्र और दबाव की राजनीति पर आधारित है।"

संपादकीय में कहा गया, नगर निगम चुनाव खत्म हो गए हैं, नतीजे आ चुके हैं। असली राजनीति अभी बाकी है, जिससे संकेत मिलता है कि मेयर का चयन आसान नहीं होगा।

दिलचस्प बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने कल अपने पार्टी कार्यकताओं से कहा कि मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) का मेयर बनाना उनका सपना है। "और अगर भगवान की इच्छा हुई तो यह सपना जरूर पूरा होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने मजाक में पूछा कि क्या ठाकरे ने "देवा" शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया है या भगवान के लिए। उन्होंने कहा, "मुझे भी "देवा" कहा जाता है, इसलिए पूछ रहा हूं।" उन्होंने आगे कहा, "ऊपर वाले भगवान ने तय कर दिया है कि मेयर महायुति का ही होगा।"

बंगाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिन मतदाताओं के नाम तार्किक विसंगति (लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी)की सूची में हैं, उनकी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए। अदालत ने कहा कि यह सूची ग्राम पंचायत भवनों, तालुका स्तर के ब्लॉक कार्यालयों और वार्ड कार्यालयों में लगाई जाए, ताकि आम लोग इसे आसानी से देख सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल में करीब 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम इस तार्किक विसंगति सूची में दर्ज हैं।

मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि जिन लोगों के नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया से प्रभावित हो सकते हैं, उन्हें अपने दस्तावेज और आपत्तियां दर्ज कराने का पूरा अवसर दिया जाए। अदालत ने निर्देश दिया कि दस्तावेज और आपत्तियां जमा करने के लिए पंचायत भवनों और ब्लॉक कार्यालयों में विशेष काउंटर/कार्यालय बनाए जाएं।

भारत का ट्रंप के गाज़ा पुनर्निमाण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निकायों के ज़रिये उसे दरकिनार करने में। ट्रंप का बोर्ड ऑफ़ पीस, एक ऐसे नेता की ओर से आया है, जो लगातार संयुक्त राष्ट्र को बेकार और अप्रासंगिक बताता रहा है। यह भारत की मूल कूटनीतिक सोच के बिल्कुल विपरीत जाता है। इसी कारण "ट्रंप संयुक्त राष्ट्र" का लेबल नई दिल्ली में कहीं ज़्यादा तीखा अर्थ रखता है।

प्रस्तावित बोर्ड की संरचना इन चिंताओं को और गहरा करती है। संयुक्त राष्ट्र के विपरीत, जो कम-से-कम औपचारिक रूप से संप्रभु समानता और सामूहिक प्रक्रियाओं पर आधारित है, यह बोर्ड नियंत्रण, पदानुक्रम और वित्तीय ताकत पर टिका हुआ दिखता है। ट्रंप की केन्द्रीय भूमिका बतौर अध्यक्ष, प्रभाव के बदले बड़े वित्तीय योगदान पर ज़ोर, और यह संकेत कि यह बोर्ड गाज़ा से आगे अन्य संघर्ष क्षेत्रों तक फैल सकता है, ये सभी वैश्विक समस्याओं के समाधान का एक ऐसा मॉडल दिखाते हैं, जो संस्थागत कम और लेन-देन आधारित अधिक है। भारत, जो स्वयं को नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थक बताता आया है, के लिए ऐसे निकाय में भागीदारी एक ऐसे उदाहरण को वैधता देने का जोखिम होगा, जो उन्हीं मानदंडों को कमज़ोर करता है, जिनका समर्थन करने का भारत दावा करता है

एक नैतिक पहलू भी है, जिसे भारत नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता। बोर्ड में फ़िलिस्तीनी प्रतिनिधित्व की सीमित व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आत्मनिर्णय के सिद्धांत से मेल नहीं खाती-एक ऐसा सिद्धांत जिसका भारत ने ऐतिहासिक रूप से, भाषणों और कूटनीति, दोनों में समर्थन किया है। भारत के इज़राइल से मज़बूत संबंध होने के बावजूद, उसने वार्ता के ज़रिये दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन किया है और पश्चिम एशिया के संघर्षों को अंतरराष्ट्रीय क़ानून और समावेशी राजनीतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में सावधानी से प्रस्तुत किया है। ऐसा शांति तंत्र, जो स्थानीय एजेंसी को हाशिये पर डालता हुआ और बाहरी हाथों में सत्ता को केन्द्रीकृत करता हुआ नज़र आए, भारतीय राजनयिकों के लिए चेतावनी की घंटी है, क्योंकि ऐसे परिणाम मूल रुप से वैधता से वंचित हो सकते हैं।

इसलिए भारत की चुप्पी को न तो अनिर्णय समझा जाना चाहिए और न ही कूटनीतिक जड़ता। यह एक सोची-समझी रणनीतिक गणना को दर्शाती है। नई दिल्ली अमेरिका की किसी पहल को सार्वजनिक रूप से खारिज करने से बचना चाहती है, खासकर भारत-अमेरिका संबंधों की व्यापक दिशा को देखते हुए। लेकिन वह अपनी प्रतिष्ठा किसी ऐसे प्रोजेक्ट को देने के लिए भी तैयार नहीं है, जिसे ट्रंप की संयुक्त राष्ट्र-विरोधी आलोचना को मान्यता देने और बहुपक्षीय संस्थानों के विकल्पों को सामान्य बनाने के रूप में देखा जा सकता है। चुप्पी भारत को आगे की गुंजाइश बनाए रखने का अवसर देती है, साथ ही उन लोगों तक असहजता का संकेत भी पहुंचाती है, जो ध्यान से सुन रहे हैं।

इस संदर्भ में बोर्ड ऑफ़ पीस की तुलना "ट्रंप संयुक्त राष्ट्र" से किए जाने का भारत-केन्द्रित अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यह अर्थ इस पर ज्यादा जोर नहीं देता कि क्या यह बोर्ड औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता है। बल्कि इस बात पर देता है कि क्या यह उस विचार को कमज़ोर करता है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा का प्रबंधन समावेशी, नियम-आधारित संस्थानों के माध्यम से होना चाहिए, न कि नेताओं द्वारा संचालित गठबंधनों के ज़रिये। भारत के लिए,जो संयुक्त राष्ट्र के भीतर अधिक आवाज़ चाहता है, न कि उसके बिना एक दुनिया, यह बोर्ड केवल शांति स्थापना में एक नवाचार नहीं, बल्कि उस बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए संभावित चुनौती है, जिसे वह दशकों से भीतर से बदलने की कोशिश करता रहा है।

नितिन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

धर्मेन्द्र प्रधान, भूपेन्द्र यादव और किरेन रिजिजू की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में निर्वाचन अधिकारी के. लक्ष्मण को नितिन नबीन के नामांकन पत्रों का एक सेट सौंपा।

इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अन्य राज्य नेताओं ने भी नबीन के समर्थन में नामांकन पत्रों का एक और सेट जमा किया। बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, झारखंड और अन्य राज्यों के नेताओं ने भी नबीन के समर्थन में नामांकन पत्र दाखिल किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, नायब सिंह सैनी और प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे।

'ग्रीनलैंड के बारे में उनकी सोच ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

घोषणा की आलोचना की है, जो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध कर रहे हैं।

यूरोपीय संघ के एंटी-कोएर्शन (दबाव विरोधी) कानून के तहत, नेता अमेरिका के खिलाफ तथाकथित "ट्रेड बाज़ूका" इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। ट्रेड बाज़ूका व्यापारिक दबाव डालने के लिए किसी देश द्वारा उठाए गए बेहद सख्त कदमों को कहा जाता है। यह प्रतिक्रिया यूरोप पर लगाए गए विशेष 10 प्रतिशत टैरिफ के खिलाफ है, जो ग्रीनलैंड पर अमेरिका के सीधे कब्जे के विरोध के कारण लगाए गए हैं।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जो ग्रीनलैंड के द्वीपवासियों के समर्थन में सबसे आगे हैं, ने अमेरिका के नए अतिरिक्त शुल्क के खिलाफ कदम उठाने की बात कही है। यही भावना अमेरिका के कथित सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन ने भी व्यक्त की है, जो लंबे समय से अमेरिका के साथ विशेष संबंध का दावा करता रहा है।

अपने दबाव विरोधी उपायों के तहत, यूरोप अपने कुछ निर्यात बाजारों तक अमेरिकन उत्पादों की पहुंच को रोक सकता है और निर्यात नियंत्रण उपाय भी लागू कर सकता है। ऐसे कदमों से अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी, दोनों को एक साथ नुकसान पहुंचेगा।

इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना बयानबाज़ी के संभावित असर पहले से ही वित्तीय बाजारों और अन्य क्षेत्रों में दिखाई देने लगे हैं। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ा है, जो अनिश्चितता के समय पसंदीदा निवेश माना जाता है। इसका यह भी मतलब है कि डॉलर कीमती स्वर्ण धातु के मुकाबले कमजोर हो रहा है।

यूरोप पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की ट्रंप की योजना के ऐलान के बाद शेयर बाजार भी प्रभावित हुए हैं। सोमवार को बाजार खुलते ही अमेरिकी सूचकांक लगभग 1 से 1.2 प्रतिशत तक गिर गए, जिससे निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। हालात साफ होने तक यह गिरावट जारी रह सकती है।

यूरोपीय कमीशन के प्रवक्ताओं ने कहा है कि इस तरह के कदम और फैसले अंततः अटलांटिक के दोनों ओर की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाएंगे और इसका बोझ अंत में आम लोगों पर पड़ेगा। यह न तो जनता के लिए फायदेमंद होगा और न ही यूरोप व अमेरिका के देशों के लिए। इन घटनाक्रमों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा करने की क्षमता है।

यूरोप के प्रति अपनी नाराज़गी को और स्पष्ट करते हुए, और अब उसके कथित कट्टर दुश्मन रूस को तरजीह देते हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गाज़ा के लिए प्रस्तावित बोर्ड फॉर पीस में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ट्रंप ने इस बोर्ड का प्रस्ताव गाज़ा में संघर्ष समाप्त होने के बाद पुनर्निर्माण की अपनी व्यापक योजना के तहत रखा है।

रूसी राष्ट्रपति के एक विशेष दूत भी स्विट्ज़रलैंड के दावोस जा रहे हैं, जहां वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। फोरम की वार्षिक बैठक हर साल स्विस स्की रिसॉर्ट दावोस में होती है, जहां आर्थिक निर्णयों में सबसे प्रभावशाली लोग आपसी बातचीत और अनौपचारिक नेटवर्किंग के लिए एकत्र होते हैं।

- **साथ ही अमेरिका के स्टॉक मार्केट में 1.2 प्रतिशत की गिरावट आयी, जिससे इन्वेस्टर्स का खर्चा बढ़ गया तथा यह स्टॉक मार्केट में गिरावट और आगे जारी रहने की आशंका है, जिससे ग्लोबल इकॉनमी की रफ्तार और धीमी पड़ेगी।**

यूएई के राष्ट्रपति को कार से लेने एयरपोर्ट पहुंचे प्र.मंत्री मोदी

नई दिल्ली, 19 जनवरी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन सोमवार को भारत के अपने आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।

दोनों नेताओं के बीच स्वागत समारोह के दौरान दोस्ताना बातचीत भी हुई। इस दौरान एक खास पल भी देखने को मिला, जब एक बार फिर पीएम मोदी की कार वाली डिप्लोमेसी की झलक देखने को मिली।

पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद साथ ही एक ही कार में एयरपोर्ट से रवाना हुए, जिससे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और दोस्ताना संबंधों की झलक दिखी।

मणिकर्णिका घाट के डोम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कानूनी याचिकाएं भी दायर की गई हैं।

विरासत स्थलों के पुनर्रूपांकन (रीडिजायनिंग) को लेकर भाजपा सरकार की प्रवृत्ति पहले भी बड़े विवादों को जन्म दे चुकी है, चाहे वह साबरमती आश्रम परियोजना हो, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना हो, काशी विश्वनाथ पुनर्विकास योजना हो, या अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक का पुनर्विकास हो।

इतिहासकार मृदुला मुखर्जी के अनुसार, समस्या इस आशंका से जुड़ी है कि पवित्र स्थलों का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे उदाहरण हैं, जहां मौजूदा संरचनाओं को बनाए रखते हुए, विरासत संरक्षण के साथ पुनर्विकास किया गया है।" रिपोर्ट बताती हैं कि मणिकर्णिका घाट के पास मॉल और बड़े व्यावसायिक ढांचे बनाने की योजनाएं हैं। मुखर्जी ने कहा, "ये योजनाएं बेतुकी हैं और इस विरासत स्थल की पवित्रता को कमज़ोर करती हैं।"

विरोध के बाद स्थल का दौरा करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी मूर्ति या संरचना को नहीं तोड़ा गया है।

पुनर्विकास योजना के तहत, शुरुआत में लगभग 3,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा और बाद में इसे 39,350 वर्ग मीटर के प्लेटफॉर्म तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे मणिकर्णिका में यह सबसे बड़ा श्मशान परिसर बन जाएगा। चार चरणों में पूरी होने वाली इस परियोजना के पूरा होने के बाद, एक साथ 19 शवदाह की सुविधा होगी और इसमें सार्वजनिक उपयोग की कई सुविधाएं भी शामिल होंगी। माना जा रहा है कि इस परियोजना की शुरुआत मणिकर्णिका के डोम राजा, विश्वनाथ चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर घाट को आधुनिक बनाने का अनुरोध किए जाने के बाद हुई।

- **मृदुला मुखर्जी के अनुसार ही विश्व में हैरिटेज (विरासत) को सुरक्षित रखते हुए उसके चारों तरफ जगह छोड़ते हुए नया निर्माण होता है।**
- **पर, सोशल मीडिया पर बुलडोज़र चलाए जाने तथा इस प्रक्रिया में धार्मिक मूर्तियों के खंडित होने की रील प्रसारित हो रही हैं तथा मु.मंत्री योगी आदित्यनाथ भी निर्माण स्थल पर पहुंचे तथा सार्वजनिक ऐलान करना पड़ा वह भी धार्मिक मूर्ति या स्ट्रक्चर को कोई क्षति नहीं पहुंची है।**

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. न